के लिए ट्राइबल की मान्यता दी जाए यह उनकी डिमांड है । हम बार –बार राज्य सरकार को लिखते हैं और इसमें अगर फर्दर इन्फर्मेशन मिलेगी तो उस पर विचार किया जाएगा । इस लिंग्युस्टिक कमुनिटी में जाट भी हैं और उसके साथ दूसरी कम्युनिटीज़ ब्राह्मण सिख आदि भी हैं, इसलिए यह भाषा के आधार पर इनको ट्राइबल की मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर कोई डिस्टिंक्टिव कल्वर के हिसाब से या उसके लिए पांच का जो क्राइटीरिया है उसके हिसाब से राज्य सरकार अगर जानकारी देगी तो हम उसके लिए अवश्य विचार कर सकते हैं । राज्य सरकार केवल पत्र लिखती है कि इनको ट्राइबल किया जाए, लेकिन इस आधार पर नहीं हो सकता है । अगर माननीय सदस्य इसकी फर्दर जानकारी देंगे, जैसे कि गद्दी और बकरवाल कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी-वाइज़ अगर ऎसी कोई प्रोपोज़ल राज्य सरकार से आए तो उस पर विचार हो सकता है ।

†**मिर्जा अब्दुल रशीदः** महोदय, जहां तक इनका ताल्लुक है तो दीज़ आर आल्सो ट्राइब्ज़ और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू-काश्मीर ने कई बार सर्वे करके बाकायदा इनको रेकमेंड किया है, वहां के गवर्नर साहब ने रेकमेंड किया है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन्होंने माना है, आनरेबल मंत्री जी को इस केस की पूरी वाकफ़ियत नहीं है, मेरी इनसे गुजारिश है कि यह मुझसे डिसकस करें और मैं समझाऊंगा कि ये उन ट्राइब्ज़ में आते हैं । वैसॆ क्राइटीरिया के हिसाब से तो गुज्जर और बकरवाल भी नहीं आ सकते थे परन्तु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज़ ए स्पेशल केस इनको किया है । मैं इनसे अपील करुंगा कि उसी आधार पर इन लोगों को भी जो उसी एरिया में रहते हैं जहां कि 20 परसेंट गुज्जर और बकरवाल रहते हैं जिनको कि इन्होंने किया है और यह अच्छी बात है, लेकिन जो 80 परसेंट लोग हैं उनमें काफी रिज़ेंटमेंट हैं ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Permission for Clinical Trials

*282. SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Drug Controller General of India (DCGI) is using discretion in granting permissions for clinical trials, bio-equivalences and marketing permissions;

(b) whether it is also a fact that often there are variations in the decisions from company to company; and

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

(c) if so, the guidelines and specific directions from his Ministry to DCGI in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. P. THAKUR) : (a) to (c) Applications for permission for Clinical Trials, Bio-equivalence studies and marketing of new drugs are examined by the New Drug Division in the office of DCG(I). The requirement for granting such approvals are specified in Rules 122A, 122B, 122C, 122D, and 122E and Schedule Y of Drugs and Cosmetics Rules. The evaluation of new drug/clinical trial is a complex process and varies according to the nature of molecule/drug, published data and information furnished by applicants. Permissions are granted after taking into account the technical requirements and not on discretion.

Kandla Port Trust

*285. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRI ANANTJRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of SHIPPING be pleased to slate :

(a) whether Government of Gujarat has requested the Government to revert part of the Kandla Port limit which was earlier part of Salaya minor port for the development of an oil terminal for Essar Refinery and other private sector refineries that may come up in future;

(b) if so, whether Government are considering to accept the request; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI VED PRAKASH P. GOYAL): (a) to (c) Government of Gujarat, from time to time, has been requesting to revert Vadinar, which was earlier part of minor port of Salaya, by de-linking it from Kandla Port limit. Vadinar was included in the limit of Kandla Port after Government of Gujarat issued notification deleting it from the limit of minor port of Salaya, while the Government of India issued notification for its inclusion in the limit of Kandla major port. The off-shore terminal developed at Vadinar presently caiers to the requirement of Koyali, Mathura and Panipat refineries. In addition, Kandla Port Trust has entered into an agreement for development of port facilities at Vadinar for Essar refinery. The request of Government of Gujarat has, therefore, not been acceded to by Government of India.